



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29 |

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2013/माघ 18, 1934

No. 29 |

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2013/MAGHA 18, 1934

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 5 फरवरी, 2013

सं. टीएएमपी/35/2008-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, इस प्राधिकरण की अधिसूचना सं. टीएएमपी/52/2007-विविध दिनांक 26 फरवरी, 2008 द्वारा महापत्तनों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अप्रकट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसरण में कांडला पत्तन पर बीओटी आधार पर चार बहुउद्देशीय बर्थों के निर्माण से संबंधित दिनांक 12 नवम्बर, 2008 को अधिसूचित आदेश सं. टीएएमपी/35/2008-केटीटी दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा अनुमोदित दरमानों की अधिसूचना के लिए रास इंफ्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/35/2008-केपीटी

मै. रास इंफ्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

.....

आवेदक

कोरम

- (i) श्रीमती रानी जाधव, अध्यक्ष
- (ii) श्री टी. एस. बालासुब्रह्मण्यम्, सदस्य (वित्त)

आदेश

(जनवरी, 2013 के 24वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कांडला पत्तन न्यास में बीओटी आधार पर चार बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों के निर्माण के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए आदेश सं. टीएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 14 अक्टूबर 2008 पारित किया था और उक्त आदेश 12 नवम्बर 2008 को राजपत्र सं. 192 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात्, भंडारण प्रभारों की वसूली की इकाई को "प्रति मी.ट." से "प्रति मी.ट. प्रतिदिन" में परिवर्तित करते हुए 1 सितम्बर 2009 को राजपत्र सं. 167 द्वारा भारत के राजपत्र में एक शुद्धिपत्र दिनांक 28 जुलाई 2009 अधिसूचित किया गया था।

2.1. इस संबंध में, हमें, रास इंफ्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) से एक पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2012 प्राप्त हुआ था। आरआईपीएल द्वारा अपने पत्र में की गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:—

- (i). हम कांडला पत्तन न्यास में बीओटी आधार पर एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ (लिविड तथा कंटेनर से इतर), बर्थ सं. 13 के निर्माण के लिए परियोजना का रियायत-प्राप्तकर्ता है। केपीटी के साथ रियायत करार 3 दिसम्बर 2009 को हस्ताक्षर किया गया था।
- (ii). आरआईपीएल की बर्थ सं. 13 में अपने परिचालन 21 जनवरी 2013 से शुरू करने की योजना है।
- (iii). इस परियोजना के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त आदेश और 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.8 के अधीन यथा अपेक्षित प्रशुल्क के सूचकांकन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 20.11 प्रतिशत लागू है जैसाकि इस प्राधिकरण द्वारा बताया गया है। परियोजना के लिए लागू अधिकतम दर का सार निम्नलिखित है:—

(क). बर्थ किराया प्रभार:

क्र. सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग			
		विदेशगामी (रु० में)		तटीय (रु० में)	
		आदेश दिनांक 14-10-08 द्वारा यथा अनुमोदित	प्रस्तावित (20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ)	आदेश दिनांक 14-10-08 द्वारा यथा अनुमोदित	प्रस्तावित (20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ)
(i).	सभी पोत	0.98	1.18	0.59	0.71

(ख). कार्गो प्रहस्तन प्रभार:

	घटक	दर प्रति टन रुपयों में			
		आदेश दिनांक 14-10-08 द्वारा यथा अनुमोदित		प्रस्तावित (20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ)	
		विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
(क).	खाद्यान्न और उर्वरक	189.18	113.51	227.22	136.34
(ख).	ताप कोयला	141.81	141.81	170.33	170.33
(ग).	कोयला (ताप कोयला से इतर), चूनापत्थर, खनिज, चीनी, नमक, आदि	141.81	85.09	170.33	102.20
(घ).	अन्य शुष्क बल्क	314.96	188.98	378.30	226.98
(ङ).	स्टील और बैग में रखा कार्गो	354.54	212.73	425.84	255.51
(च).	लकड़ी की लट्टे	567.58	340.55	681.72	409.03

(ग). भंडारण प्रभार:

(i). आयात के लिए (दर प्रति टन रु० में प्रतिदिन) कोई प्रभार नहीं
1 से 5 दिनों के लिए

क्र. सं.	घटक	आदेश दिनांक 14-10-08 द्वारा यथा अनुमोदित	प्रस्तावित (20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ)
	सभी प्रकार के कार्गो		
(i).	1 से 5 दिनों के लिए कोई प्रभार नहीं	0.00	0.00
(ii).	6 दिनों से 12 दिनों के लिए दर	10.00	12.01
(iii).	13 दिनों से 19 दिनों के लिए दर	15.00	18.02
(iv).	20 दिनों से आगे के लिए दर	20.00	24.02

(ii). निर्यात के लिए (दर प्रति टन रु० में प्रतिदिन)

क्र. सं.	घटक	आदेश दिनांक 14-10-08 द्वारा यथा अनुमोदित	प्रस्तावित (20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ)
	सभी प्रकार के कार्गो		
(i).	1 से 15 दिनों के लिए कोई प्रभार नहीं	0.00	0.00
(ii).	16 दिनों से 22 दिनों के लिए दर	10.00	12.01
(iii).	23 दिनों से 29 दिनों के लिए दर	15.00	18.02
(iv).	30 दिनों से आगे के लिए दर	20.00	24.02

(घ). विविध प्रभार:

घटक	आदेश दिनांक 14-10-08 द्वारा यथा अनुमोदित	प्रस्तावित (20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ)
सभी प्रकार के कार्गो	15.56	18.69

2.2. 14 अक्टूबर 2008 के अनुमोदित दरमान को दर्शाते हुए दरमानों की प्रति और प्रस्तावित दरमान संलग्न करते हुए, आरआईपीएल ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि बर्थ सं. 13 के परिचालन के लिए दरमान अधिसूचित किए जाएं।

3. केपीटी ने कांडला पत्तन में बोओटी आधार पर बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ सं. 13 के विकास की परियोजना का कार्य मै0 रास इंफ्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) को सौंपा गया है। केपीटी के साथ रियायत करार 3 दिसम्बर 2009 को हस्ताक्षर किया गया था और यह करार रियायत देने की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। उक्त रियायत करार के अनुच्छेद 8.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि रियायत-प्राप्तकर्ता परिशिष्ट-12 में दी गई प्रशुल्क अधिसूचना के अनुसार परियोजना सुविधाओं तथा सेवाओं के प्रयोक्ताओं से प्रशुल्क वसूल करने के लिए हकदार होगा। परिशिष्ट-12 चार बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों के निर्माण के लिए अप्रॉफिट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के कवर के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरमान है।

4. आरआईपीएल के पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2012 की प्रति हमारे पत्र दिनांक 5 दिसम्बर 2012 द्वारा केपीटी, लाइसेंसदाता, को टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए अप्रेषित की गई थी। अनुस्मारक के बाद, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2012 द्वारा प्रत्युत्तर दिया था। केपीटी का प्रतिसाद नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	मै. आरआईपीएल टिप्पणियां	केपीटी टिप्पणियां
1.		प्रस्तावित दरमान में टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/35/2008 दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के अनुबंध- IV के अनुच्छेद 1.1 और 1.2 के अनुसार "परिभाषाएं" "सामान्य निबंधन तथा शर्तें" भी शामिल होनी चाहिए (जिसे मै. आरआईपीएल द्वारा शामिल नहीं किया गया है)
2.		मै. आरआईपीएल के पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2012 में, मै. आरआईपीएल ने सूचित किया है कि वे घटकों/कार्गो जिसमें "कोयला" शामिल है, का प्रहस्तन करेंगे। हमारा रियायत-प्राप्तकर्ता से यह अनुरोध है कि वह यह उल्लेख करे कि क्या "ताप कोयला" प्रहस्तित किया जाएगा अथवा नहीं क्योंकि ताप कोयला प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क 31/3/2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.3 तथा 6.1.2 के अनुसार रियायती प्रशुल्क नहीं होगा।
3.	बर्थ किराया प्रभार	(i). 20.11 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रस्तावित अधिकतम दर रु0 में प्रति जीआरटी प्रति घंटा उस समय से उल्लिखित की जानी चाहिए जबसे यह प्रभावी होनी हो। (ii). टिप्पणी (v) में, दूसरी पंक्ति में, शब्द "अथवा" टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/35/2008 दिनांक 14 अक्टूबर 2008 की तुलना में बदला गया है (पंक्ति देखें: गलत सिग्नल इंजन के तैयार नहीं होने की वजह से अथवा कार्गो परिचालन के पूरा नहीं होने ...) (iii). प्रथम पंक्ति में शब्द "निष्क्रिय" को टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/35/2008 दिनांक 14 अक्टूबर 2008 की तुलना में "है" से बदला गया है (पंक्ति देखें "उस अवधि के लिए बर्थ किराया वसूल नहीं किया जाएगा जब पोत अपने बर्थ पर "ओडल्स" रहता है ...")
4.	कार्गो प्रहस्तन प्रभार	(i) 20.11 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रस्तावित अधिकतम दर रु0 में प्रति टन उस समय से उल्लिखित किया जाना चाहिए जबसे यह प्रभावी हो।
5.	भंडारण प्रभार (आयातित तथा निर्यात किए जाने वाले के लिए)	(i) टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/35/2008 दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के अनुबंध- IV के अनुसार निम्नलिखित लाइन जोड़ी जानी चाहिए। "स्वीकृत की गई निःशुल्क अवधि के बाद स्टेकयार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नवत् होगा" (ii) 20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ प्रस्तावित अधिकतम दर रु0 में प्रति टन प्रतिदिन उस समय से उल्लिखित किया जाना चाहिए जब से यह लागू होना हो को कार्गो के आयात तथा निर्यात दोनों के लिए उल्लिखित किया जाना चाहिए। (iii) टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/35/2008 दिनांक 14 अक्टूबर 2008, और शुद्धिपत्र जी.सं. 167 दिनांक 01 सितम्बर 2009 अर्थात् दर रु0 में प्रति मी.ट. प्रतिदिन के अनुसार इकाई में पुनः तैयार किया जाना चाहिए।
6.	विविध प्रभार	(i) 20.11 प्रतिशत की दर से वृद्धि के साथ प्रस्तावित अधिकतम दर रु0 में प्रति टन प्रतिदिन उस समय से उल्लिखित किया जाना चाहिए जब से यह लागू होना हो।
7.	उपर्युक्त अनुसूची (1) से (4) के लिए सामान्य टिप्पणी	प्रस्तावित अधिकतम दर में 20.11 प्रतिशत तक पहले ही वृद्धि की जा चुकी है जो 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच नहीं आती है। बजाय, रियायत-प्राप्तकर्ता 1 जनवरी 2012 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी को यहां शामिल करते हुए शुद्धि करेगा। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया

		जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावी रहेंगी।
8.	केपीटी अपने दरमान के अनुसार सिवाय बर्थ उच्चतर प्रभारों के बल्क पोतों पर सभी अन्य पोत संबंधित प्रभारों की वसूली तथा संग्रहण करेगा। (अग्रेषण पत्र का बिन्दु ज)	शब्द "बल्क" हटाया जाना अपेक्षित है और शब्द "उच्चतर" को "किराया" से परिवर्तित किया जाए, पंक्ति देखें "केपीटी दरमान के अनुसार बर्थ किराया प्रभारों के सिवाय पोतों पर सभी अन्य पोत संबंधित प्रभार वसूल तथा संग्रहित करेगा।

5.1. अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि वाणिज्यिक परिचालनों की शुरुआत से पहले, निजी परिचालक, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन यथा अपेक्षित, अपने परिचालनों के लिए लागू अधिकतम दरों वाले दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण का रुख करेगा। अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि खंड 2.9.1 के अनुसार टीएमपी द्वारा निर्धारित किया जाने वाला दरमान पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क सीमाओं के अनुसार होगा और बोली दस्तावेज में शामिल किया जाएगा, परन्तु खंड 2.8 में स्पष्ट किए गए सूचकांकन के अधीन। ऐसा दरमान तथा शर्तों का विवरण इस प्राधिकरण द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। ये प्रावधान नवम्बर 2009 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में भी किए गए हैं।

5.2. महापत्तनों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2008 के खंड 2.8 के अनुसार, प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी परन्तु 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही, और समायोजित प्रशुल्क प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी होगा।

5.3. अपफ्रंट प्रशुल्क के लिए आधार वर्ष और 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी तदनुसूची वार्षिक वृद्धि हमारे पत्र सं. टीएमपी/12/2009—विविध दिनांक 18 अप्रैल 2012 द्वारा केपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को पहले ही संप्रेषित किए जा चुके हैं जोकि निम्नवत् हैं:-

निम्नलिखित तारीख को आधार डब्ल्यूपीआई के साथ प्रशुल्क	वृद्धि कारक लागू किया जाएगा
1 जनवरी 2011	5.89%
1 जनवरी 2010	12.18%
1 जनवरी 2009	13.71%
1 जनवरी 2008	20.11%

5.4. संदर्भित सुविधा के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के दरमान के खंड 6 (अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी) के अनुसार, प्रशुल्क सीमाएं 1 जनवरी 2008 से प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले डब्ल्यूपीआई में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक सूचकांकित की जाएंगी। तदनुसार, संदर्भित मामले में लागू किया जाने वाला वृद्धि कारक दरमान के खंड 6 के साथ पठित हमारे पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2012 के अनुसार 20.11 प्रतिशत है।

6.1. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i). इस प्राधिकरण ने बीओटी आधार पर चार बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों के निर्माण के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के

आधार पर अप्रकट प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए एक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 पारित किया था। केपीटी ने बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ सं. 13 के निर्माण की परियोजना में 0 रास इम्फोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) को सौंपी है और 3 दिसम्बर 2009 को 30 वर्षों की अवधि के लिए रियायत करार किया है।

- (ii). जैसाकि पहले बताया गया है, अप्रकट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.9.1. निजी परिचालक से यह अपेक्षा करता है कि वह वाणिज्यिक परिचालनों की शुरुआत से पहले अपने परिचालनों पर लागू अधिकतम दरों वाले दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण का रुख करना होगा। तदनुसार, आरआईपीएल ने 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन यथा अपेक्षित दरमान अधिसूचित करने के अनुरोध के साथ इस प्राधिकरण का रुख किया है।
- (iii). आरआईपीएल द्वारा यथा प्रतिवेदित, परिचालक उम्मीद करता है कि वाणिज्यिक परिचालन 221 जनवरी 2013 से शुरू होंगे। आरआईपीएल द्वारा प्रतिवेदित स्थिति पर विश्वास करते हुए, यह प्राधिकरण अक्टूबर 2008 में अनुमोदित दरमान की अधिसूचना के लिए आरआईपीएल के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए प्रवृत्त है परन्तु डब्ल्यूपीआई के लिए यथा अनुमोदित की गई दरों के सूचकांकन के संदर्भ में 60 प्रतिशत की सीमा तक समायोजन करना होगा।
- (iv). केपीटी, लाइसेंसदाता होने के नाते, जिससे आरआईपीएल के प्रस्ताव पर टिप्पणियां मांगी गई थीं, ने प्रस्तावित दरमान पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं, जिनपर नीचे चर्चा की गई है:-
 - (क). जैसाकि केपीटी द्वारा सही बताया गया है, आरआईपीएल द्वारा प्रस्तावित दरमान में अप्रकट प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के साथ अधिसूचित किए गए दरमान के खंड 1.1 (परिभाषाएं) और 1.2 (सामान्य निबंधन तथा शर्तें) शामिल नहीं किए गए हैं। ये खंड आरआईपीएल द्वारा प्रस्तावित मसौदा दरमान में शामिल किए गए हैं।
 - (ख). केपीटी द्वारा उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में क्या आरआईपीएल ताप कोयला का प्रहस्तन करेगी नहीं, अप्रकट प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा अधिसूचित दरमान में "ताप कोयला" भी शामिल किया गया है।
 - (ग). बर्थ किराये की घटना के समय के संदर्भ में, बर्थ किराये की अवधि टिप्पणी (i) से खंड 2 (बर्थ किराया प्रभार) में यथा विनिर्दिष्ट बर्थ के समय पोत अभिग्रहण से गिनती की जाएगी।
 - (घ). आरआईपीएल द्वारा प्रस्तावित दरमान में टिप्पणी (v) से खंड 2 (बर्थ किराया प्रभार) की दूसरी पंक्ति और टिप्पणी (iii) से खंड 2 (बर्थ किराया प्रभार) की प्रथम पंक्ति में केपीटी द्वारा इंगित की गई कमियां टाइपलेखन त्रुटि प्रतीत होती हैं जिन्हें सही कर दिया गया है।
 - (ङ). अक्टूबर 2008 के अप्रकट प्रशुल्क आदेश में अधिसूचित दरमान के खंड 4 (भंडारण प्रभार) में निर्दिष्ट वाक्य "स्वीकृत की गई निःशुल्क अवधि के बाद स्टेकयार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नवत् होंगे" आरआईपीएल द्वारा प्रस्तावित मसौदा दरमान में शामिल नहीं है जैसाकि केपीटी द्वारा बताया गया है। उक्त वाक्य दरमान में शामिल किया गया है।
 - (च). केपीटी ने दर्शाने की कोशिश की है जब दरमान प्रभावी होगा। चूंकि बीओटी परिचालक उस दिन से प्रभार वसूल करने की स्थिति में अवश्य होना चाहिए जब से परिचालक अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू करता है, इसलिए यह उपयुक्त है कि दरमान केपीटी

के बर्थ सं. 13 में वाणिज्यिक परिचालनों की शुरुआत की तारीख से लागू किया गया है।

- (छ). केपीटी द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर कि वृद्धि कारक के अनुप्रयोजन के लिए सुविचारित किया जाने वाला आधार वर्ष 2012 और 2008 होना चाहिए, यह बताया गया है कि अक्टूबर 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के दरमान के खंड 6 (अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणियाँ) के अनुसार 1 जनवरी 2008 से प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले डब्ल्यूपीआई में 60 प्रतिशत तक की भिन्नता 2008 में अधिसूचित की गई प्रशुल्क सीमाओं पर लागू की जानी चाहिए।
- (च). केपीटी ने सिवाय बर्थ किराया प्रभारों के केपीटी द्वारा पोत संबंधित प्रभारों की वसूली के संबंध में अपने कवरिंग पत्र में आरआईपीएल द्वारा किए उल्लेख में कुछ शुद्धियों का सुझाव दिया है। केपीटी द्वारा उन पोतों पर सिवाय बर्थ किराये के पोत संबंधित प्रभारों की वसूली तथा संग्रहण जो बर्थ सं. 13 आएंगे, केपीटी तथा आरआईपीएल के बीच हुए रियायत करार द्वारा शासित है और अक्टूबर 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क के अधीन अधिसूचित दरमान द्वारा शासित नहीं है।
- (v). 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार, खंड 2.9.1 के अनुसार निजी परिचालक के लिए इस प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया दरमान पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क सीमाओं के अनुसार होना चाहिए और बोली दस्तावेज में शामिल किया गया है, परन्तु पहले स्पष्ट किए गए सूचनकांकन के अधीन। आरआईपीएल द्वारा केपीटी के साथ किए गए रियायत करार का परिशिष्ट-12 शुद्धिपत्र दिनांक 28 जुलाई 2009 के साथ पठित चार बहुउद्देशीय कागोर्क बर्थों के निर्माण के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय प्रशुल्क आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के कवर के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरमान देखा गया है।
- (vi). 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 2.8 के अधीन यथा अपेक्षित आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क के सूचकांकन के संदर्भ में, 20.11 प्रतिशत का वृद्धि कारक नवम्बर 2008 में अधिसूचित प्रशुल्क सीमाओं पर लागू किया जाना है। नवम्बर 2008 में अधिसूचित प्रशुल्क सीमाओं पर 20.11 प्रतिशत का वृद्धि कारक लागू करते हुए, आरआईपीएल द्वारा क्रियान्वयन-योग्य दरमान अक्टूबर 2008 के प्रशुल्क आदेश में यथा निर्धारित दरों के अनुप्रयोजन को शासित करने वाली शर्तों के साथ तैयार किया गया है। यहां पर यह नोट किया जाना है कि अक्टूबर 2008 के आदेश द्वारा अधिसूचित केवल प्रशुल्क मदों की दरें ही लागू किए जाने योग्य वृद्धि कारक के अनुप्रयोजन तथा अक्टूबर 2008 के आदेश में यथा शामिल की गई दरों को लागू करने वाली सभी शर्तें बिना किसी बदलाव के रहेंगी।
- (vii). जैसाकि अक्टूबर 2008 के प्रशुल्क आदेश के पैरा 10.3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, दिशानिर्देशों के खंड 3.8.5 के अनुसार, दरमान के स्पष्टीरणों या निर्वर्चन की अपेक्षा वाला कोई प्रश्न उठता है तो वह मामला इस प्राधिकरण को भेजा जाएगा और इस संबंध में इसका निर्णय परिचालक पर बाध्यकारी होगा।
- (viii). आरआईपीएल से यह उम्मीद की जाती है कि बोली दस्तावेजों/रियायत करार में दिए गए निष्पादन मानकों पर कम से कम निष्पादन करे। आरआईपीएल का वास्तविक कार्यनिष्पादन इस प्राधिकरण द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। यदि सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत आती है तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोप की जांच करेगा और अपने निष्कर्ष कांडला पत्तन न्यास को अग्रेषित करेगा। यदि आरआईपीएल के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी होगी तो कांडला पत्तन न्यास रियायत करार की शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।

- (ix). टर्मिनल पर वाणिज्यिक परिचालन के दौरान, प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर, आरआईपीएल कांडला पत्तन न्यास के माध्यम से इस प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछले तीन महीनों के दौरान बर्थ के प्रत्यक्ष तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन शामिल होंगे।

6.2. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केपीटी में आरआईपीएल द्वारा परिचालित किए जाने वाले बहुउद्देशीय बर्थ सं. 13 के लिए दरमान अधिसूचित करता है जो अनुबंध रूप में संलग्न किया गया है।

6.3. आरआईपीएल के लिए अधिसूचित दरमान केपीटी में आरआईपीएल द्वारा वाणिज्यिक परिचालनों की शुरुआत की तारीख से लागू होगा।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/12/असा.]

अनुबंध

रास इंफ्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड दरमान

1.1. परिभाषाएँ

इस दरमान में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:-

- (i). "तटीय पोत" का अभिप्राय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से विनियुक्त पोत से है।
- (ii). "विदेशी पोत" का अभिप्राय तटीय पोतों से इतर किसी पोत से है।
- (iii). "प्रतिदिन" का अभिप्राय प्रति केलेंडर दिवस से है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

1.2. सामान्य निबंधन और शर्तें

- (i) पोत की हैसियत, सीमाशुल्क अथवा महानिदेशक, नौवहन द्वारा जैसा इसका प्रमाणन किया गया है, पोत संबंधित प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए 'तटीय' अथवा 'विदेशगामी' पोत के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक कारक है, और, कार्गो की प्रकृति अथवा इसका मूल इस प्रयोजन के लिए किसी प्रकार से प्रासंगिक नहीं होगा।
- (ii). (क). सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के तदनुरूपी प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
(ख). ताप कोयला से इतर सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
(ग). कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायती दरें जलयान-तट स्थानांतरण और घाट से/घाट को भंडारण यार्ड को/से स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर घाटशुल्क सहित प्रभार्य होनी चाहिए।
(घ). विदेशी पत्तन से कार्गो, जोकि भारतीय पत्तन 'ख' पर अनुवर्ती पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' पर पहुंचता है, से इसके तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार प्रभार्य होंगे। अन्य शब्दों में, तटीय नौचालन करने की अनुमति वाले पोत द्वारा भारतीय पत्तनों से/पर वहन किया जाने वाला कार्गो रियायत के लिए पात्र होगा।
- (iii). विलंबित भुगतानों/वापसियों पर ब्याज:
(क). उपयोक्ता विलंबित भुगतानों पर इस दरमान के अधीन दंडात्मक ब्याज अदा करेगा। इसी प्रकार, टर्मिनल प्रचालक विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।
(ख). दंडात्मक ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।

- (ग). वापसियों में विलंब सेवाओं के पूरा होने की तारीख से अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो, से केवल 20 दिन गिना जाएगा।
- (घ). उपयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिल दिए जाने के पश्चात केवल 10 दिन गिना जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां सेवाएं प्राप्त करने से पहले भुगतान किया जाता है जहां प्रभारों का अग्रिम भुगतान इस दरमान में एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है।

(iv). परिगणित सभी प्रभार बिल के कुल जोड़ पर अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किए जाएंगे।

(v). उपयोक्ताओं को प्रचालक पर आरोप्य उपयुक्त स्तर से अधिक विलंब के लिए प्रभार अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. बर्थ किराया प्रभार:

मास्टरों/स्वामियों/पोत के एजेंटों और पहुंचने वाले अथवा पत्तन के समीप पड़े अन्य फ्लोटिंग क्राफ्ट द्वारा देय बर्थ किराया प्रभार नीचे दी गई दरों के अनुसार होंगे:-

क्र.सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग	
		विदेशगामी पोत (रुपया में)	तटीय पोत (रुपया में)
1.	सभी पोत	1.18	0.71

टिप्पणियाँ:

- (i). बर्थ किराये की अवधि पोत द्वारा बर्थ के अभिग्रहण के समय से परिकलित की जाएगी।
- (ii). बर्थ किराये में बर्थ पर प्रदत्त सेवाओं, जैसे - बर्थ का अभिग्रहण, कूड़ा हटाना, बर्थों की सफाई, फॉयर वॉच, आदि के प्रभार शामिल हैं।
- (iii). जब कोई पोत टर्मिनल प्रचालक के उपस्कर के खराब होने अथवा बिजली के कारण अथवा टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य किन्हीं अन्य कारणों से इसके बर्थ में लगातार एक घंटा अथवा उससे अधिक निष्क्रिय रहता है तो उस अवधि के लिए बर्थ किराया वसूल नहीं किया जाएगा।
- (iv). (क). बर्थ किराया पोत द्वारा नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत देने के समय के 4 घंटों बाद रूक जाएगा।
- (ख). बर्थ किराये की समाप्ति के लिए निर्धारित 4 घंटों की समय सीमा पक्षीय ज्वारभाटा परिस्थितियों, खराब मौसम, और रात्रि नेविगेशन की कमी के कारण से जलयान के प्रतीक्षा समय से अतिरिक्त होगी।
- (ग). पोत का मास्टर/एजेंट नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत केवल पक्षीय ज्वारभाटा और मौसम परिस्थितियों के अनुसार ही देगा।
- (v). दंडात्मक बर्थ किराया गलत संकेत के लिए एक दिन (24 घंटे) के बर्थ किराया प्रभार के समकक्ष होगा।

“गलत संकेत” तब माना जाएगा, जब कोई पोत तैयार होने का संकेत दे देता है और अनुमान से पाइलट की माँग कर देता है, जबकि वह पोत इंजन के तैयार न होने या कार्गो प्रचालन पूरा न होने या पोत के कारण किसी अन्य वजह से बर्थ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसमें तैयारी का वह संकेत शामिल नहीं है, जब कोई पोत प्रतिकूल ज्वारभाटा, रात्रि नौचालन की कमी या खराब मौसम स्थितियों के कारण प्रस्थान नहीं कर पाता है।”

3. कार्गो प्रहस्तन प्रभार:

कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट की गई दरों पर कार्गो के आयातक द्वारा सीधे विनिहित कार्गो पर देय होंगे:-

क्र.सं.	घटक	दर रुपयों में (प्रति टन)	
		विदेशी	तटीय
(क).	खाद्यान्न और उर्वरक	227.22	136.34
(ख).	ताप कोयला	170.33	170.33
(ग).	कोयला (ताप कोयला से इतर), चूनापत्थर, खनिज, चीनी, नमक, आदि	170.33	102.20

(घ).	अन्य शुष्क बल्क	378.30	226.98
(ङ).	स्टील और बैग में रखा कार्गो	425.84	255.51
(च).	लकड़ी की लट्टे	681.72	409.03

टिप्पणी:

ऊपर निर्धारित प्रहस्तन प्रभार इनके लिए समेकित प्रभार है — (i) पोत से कार्गो की उतराई, नौभरण और भंडारण के बिन्दु तक उसका स्थानांतरण सहित, 5 दिनों की निःशुल्क अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण और आयात कार्गो के मामले में ट्रकों पर लदाई और (ii) स्टेकयार्ड पर ट्रकों से कार्गो की उतराई, 15 दिनों की निःशुल्क अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण, लदाई बिन्दु पर कार्गो स्थानांतरण और जलयान पर लदाई, नौभरण सहित। इस समेकित प्रभार में घाटशुल्क और लेबर की आपूर्ति, जहां कहीं जरूरी हो, शामिल है।

4. भंडारण प्रभार:

निःशुल्क अवधि के बाद स्टेकयार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नलिखित होंगे:-

(क). आयात के लिए

(दर रुपयों में प्रति मी०ट० प्रतिदिन)

क्र.सं.	घटक	दर छठे दिन से बारहवें दिन	दर तेरहवें दिन से उन्नीसवें दिन	दर बीसवें दिन से आगे के लिए
(क).	सभी प्रकार के कार्गो	12.01	18.02	24.02

(ख). निर्यात के लिए

(दर रुपयों में प्रति मी०ट० प्रतिदिन)

क्र.सं.	घटक	दर सोलहवें दिन से बाइसवें दिन	दर तेइसवें दिन से उनत्तीसवें दिन	दर तीसवें दिन से आगे के लिए
(क).	सभी प्रकार के कार्गो	12.01	18.02	24.02

उपर्युक्त खंड 4 (क) और 4 (ख) के लिए टिप्पणियाँ:

- आयात कार्गो के लिए पाँच निःशुल्क दिवस और निर्यात कार्गो के लिए पन्द्रह निःशुल्क दिवस स्वीकार्य होंगे। निःशुल्क अवधि के परिकलन के प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के अकार्यदिवस अतिरिक्त होंगे।
- निर्धारित निःशुल्क दिवसों के बाद कार्गो के विराम के लिए भंडारण प्रभार टर्मिनल के अकार्य-दिवसों और सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश-दिवसों सहित सभी कार्य दिवसों के लिए देय होगा।
- कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोदभूत नहीं होगा जब उपयोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर टर्मिनल प्रचालक अपने ऊपर आरोप्य कारणों से कार्गो की सुपुर्दगी/नौभरण की स्थिति में नहीं हो।

5. विविध प्रभार

क्र.सं.	घटक	दर रुपयों में (प्रति टन)
(क).	सभी प्रकार के कार्गो	18.69

ऊपर निर्धारित विविध प्रभार सभी विविध सेवाओं जैसे - घाट पर कार्गो की सफाई, कार्गो को तोलना, धूल निवारण आदि के प्रावधान के लिए समेकित प्रभार है।

6. उपर्युक्त अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी:

प्रशुल्क सीमाएँ मुद्रास्फीति से सूचकांकित होंगी परंतु 1 जनवरी, 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच प्रोदभूत होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत तक। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वचालित समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएँ प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी होंगी।

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th February, 2013

No. TAMP/35/2008-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Ras Infraport Private Limited for notification of Scale of Rates approved vide Order No. TAMP/35/2008-KPT dated 14th October, 2008 notified on 12th November, 2008 vide Gazette No. 192 pertaining to Construction of four Multipurpose Berths on BOT basis at Kandla Port in pursuance of the guidelines for upfront tariff setting for Public Private Participation (PPP) projects at Major Ports vide this Authority's Notification No. TAMP/52/2007-Misc. dated 26th February, 2008 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/35/2008-KPT

M/s. Ras Infraport Private Limited

Applicant

.....
QUORUM

- (i) Smt. Rani Jadhav, Chairperson
(ii) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

ORDER

(Passed on this 24th day of January, 2013)

This Authority had passed an Order No. TAMP/35/2008-KPT dated 14 October 2008 fixing upfront tariff based on the proposal filed by the Kandla Port Trust (KPT) for fixation of upfront tariff for construction of four multipurpose cargo berths on BOT basis at Kandla Port Trust and the said order was notified in the Gazette of India on 12 November 2008 vide Gazette No. 192. Subsequently, a Corrigendum dated 28 July 2009 was notified in the Gazette of India on 1 September 2009 vide Gazette No. 167 changing the unit of levy of storage charges from "per MT" to "per MT per day".

2.1. In this connection, we have received a letter dated 20 November 2012 from Ras Infraport Private Limited (RIPL). The main points made by RIPL in its letter are summarized below:

- (i). We are the concessionaire of the project for construction of Berth 13, a multipurpose cargo berth (other than liquid and container) on BOT basis at Kandla Port Trust. The Concession Agreement with KPT has been signed on 3 December 2009.
- (ii). RIPL plans to commence its operations at Berth No. 13 w.e.f. 21 January 2013.
- (iii). The upfront tariff for this project has been fixed by the Authority's order dated 14 October 2008. As per the said order and the indexation of tariff as required under clause 2.8 of the tariff guidelines of 2008, 20.11% is applicable for the financial year 2012-13 as intimated by the Authority. Following is the summary of ceiling rate applicable for the project:

(a). Berth Hire Charges:

Sl. No.	Vessels	Rate per GRT per hour or part thereof			
		Foreign Going (In ₹)		Coastal (In ₹)	
		As approved vide Order dtd. 14.10.08	Proposed (with escalation of @ 20.11%)	As approved vide Order dtd. 14.10.08	Proposed (with escalation of @ 20.11%)
(i).	All vessels	0.98	1.18	0.59	0.71

(b). Cargo Handling Charges:

	Commodity	Rate per Tonne in Rupees			
		As approved vide Order dtd. 14.10.08		Proposed Ceiling rate (with escalation of @ 20.11%)	
		Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
(a).	Food grains and Fertilisers	189.18	113.51	227.22	136.34
(b).	Thermal Coal	141.81	141.81	170.33	170.33
(c).	Coal (other than thermal coal), limestone, Minerals, Sugar, Salt, etc.	141.81	85.09	170.33	102.20
(d).	Other dry bulk	314.96	188.98	378.30	226.98
(e).	Steel and Bagged cargo	354.54	212.73	425.84	255.51
(f).	Timber logs	567.58	340.55	681.72	409.03

(c). Storage Charges:

(i). For IMPORT (Rate per tonne in ₹ per day) No charges for 1 to 5 days

Sl. No.	Commodity	As approved vide Order dtd. 14.10.08	Proposed (with escalation of @20.11%)
	All types of Cargo		
(i).	No charges for 1 to 5 days	0.00	0.00
(ii).	Rate for 6 days to 12 days	10.00	12.01
(iii).	Rate for 13 Days to 19 Days	15.00	18.02
(iv).	Rate for 20 days onwards	20.00	24.02

(ii). For EXPORT (Rate per tonne in ₹ per day)

Sl. No.	Commodity	As approved vide Order dtd. 14.10.08	Proposed (with escalation of @20.11%)
	All types of Cargo		
(i).	No charges for 1 to 15 days	0.00	0.00
(ii).	Rate for 16 days to 22 days	10.00	12.01
(iii).	Rate for 23 Days to 29 Days	15.00	18.02
(iv).	Rate for 30 days onwards	20.00	24.02

(d). Miscellaneous Charges:

Commodity	As approved vide Order dtd. 14.10.08	Proposed (with escalation of @ 20.11%)
All types of Cargo	15.56	18.69

2.2. Enclosing a copy of the Scale of Rates depicting the approved Scale of Rates of 14 October 2008 Order and the proposed Scale of Rates, the RIPL has requested this Authority to notify the Scale of Rates for operation of Berth No. 13.

3. The KPT has awarded the project of Development of Multipurpose Cargo Berth No.13 on BOT basis at Kandla Port to M/s.Ras Infraport Private Limited (RIPL). The Concession Agreement with KPT has been signed on 3 December 2009 and the agreement is valid for a period of 30 years from the date of award of concession. Article 8.1 of the said Concession Agreement stipulates that the concessionaire shall be entitled to recover tariff from the users of the project facilities and services as per the tariff notification set out in Appendix -12. The Appendix - 12 is the Scale of Rates notified by this Authority under cover of the tariff Order dated 14 October 2008 fixing upfront tariff for construction of four multipurpose cargo berths.

4. A copy of RIPL's letter dated 20 November 2012 was forwarded vide our letter dated 5 December 2012 to the KPT, Licensor, inviting its comments. After a reminder, the KPT vide its letter dated 31 December 2012 has responded. The response of the KPT is given below:

Sl. No.	M/s. RIPL Observations	KPT comments
1.		The Proposed Scale of Rates should also contain the "Definitions" "General terms and Conditions" as per Article 1.1 and 1.2 of Annex-IV of TAMP Order No.TAMP/35/2008 dated 14 October 2008 (which has not been included by M/s.RIPL)
2.		In the letter of M/s.RIPL dated 20th November 2012, M/s.RIPL informed that they will handle the commodities/cargo which includes "coal". We kindly request the Concessionaire to mention whether "Thermal Coal" will be handled or not as the tariff for thermal coal handling will not have concessional tariff as per clause 4.3 and 6.1.2 of Tariff Guidelines notified in Gazette of India on 31/3/2005.
3.	Berth Hire Charges	(i). The proposed ceiling rate in ₹ per GRT per hour with escalation @ 20.11% should be mentioned with point of time from which it is to be effective.

		(ii). In the note (v), in 2nd Line, the word "or" is replaced by word compared to TAMP order No. TAMP/35/2008 dated 14 October 2008 (the line refers to: False signal would be.. due to engine not being ready or cargo operation not completed...)
		(iii). In first line the word "idles" is replaced by word "is" as compare to TAMP order no. TAMP/35/2008 dated 14 October 2008 (the line refers to "No berth hire shall be levied for the period when the vessel "odles" at its berth for continuous...")
4.	Cargo Handling Charges	(i) The proposed ceiling rate in ₹ per tonne with escalation @ 20.11% should be mentioned with point of time from which it is to be effective.
5.	Storage Charges (For cargo imported and to be exported)	(i) The following line should be added as per the Annex-IV of TAMP order No. TAMP/35/2008 dated 14 October 2008. "The storage charges for the cargo stored in the stackyard beyond the free period allowed shall be as below" (ii) The proposed ceiling rate in ₹.per tonne per day with escalation @ 20.11% should be mentioned with point of time from which it is to be effective should be mentioned for both Import and Export of Cargo. (iii) Reframe the unit in accordance with TAMP order No. TAMP/35/2008 dated 14 October 2008, and the Corrigendum GNo.167 dated 01 Sept 2009 i.e., Rate in ₹ per MT per day.
6.	Miscellaneous Charges	(i) The proposed ceiling rate in ₹ per tonne with escalation @ 20.11% should be mentioned with point of time from which it is to be effective.
7.	General Note to Schedule (1) to (4) above	The proposed ceiling rate is already escalated by 20.11% so it cannot occur between 1 Jan 2008 and 1 Jan of relevant year. Instead, the Concessionaire shall make a correction hereby incorporating 1st Jan 2012 and 1st Jan of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force 1st April 13 to 31st March 2014.
8.	The KPT will levy and collect all other vessel related charges on the bulk vessels except berth higher charges as per its Scale of Rates. (Point h of forwarding letter)	Word "bulk" required to be deleted and the word "higher" may be replaced as "hire" the line refers to "the KPT will levy and collect all other vessel related charges on the vessels except berth hire charges as per the scale of rates.

5.1. Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff stipulates that before commencement of commercial operations, the private operator shall approach this Authority for notification of Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations, as required under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963. Clause 2.9.2. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff stipulates that the Scale of Rates to be framed by TAMP as per Clause 2.9.1. shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document, subject to indexation explained in Clause 2.8. Such Scale of Rates and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963. These provisions have also been made in the upfront tariff Order of November 2009.

5.2. As per clause 2.8 of guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Ports, 2008, the Tariff Caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year, and the adjusted tariff will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

512 GI/13-4

5.3. The base year for the upfront tariff and the corresponding annual escalation with effect from 1 April 2012 were already communicated to all the Major Port Trusts including KPT vide our letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 18 April 2012 as given below:

Tariff with base WPI as on	Escalation factor to be applied
1 January 2011	5.89%
1 January 2010	12.18%
1 January 2009	13.71%
1 January 2008	20.11%

5.4. As per clause 6 [General Note to Schedule (2) to (5)] of the Scale of Rates of the upfront tariff Order dated 14 October 2008 fixing upfront tariff for the facility in reference, tariff caps will be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year. Accordingly, the escalation factor to be applied in the case in reference is 20.11% as per our letter dated 18 April 2012 read with clause 6 of the Scale of Rates.

6.1. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). This Authority has passed an Order dated 14 October 2008 fixing upfront tariff based on the proposal filed by the Kandla Port Trust (KPT) for fixation of upfront tariff for construction of four multipurpose cargo berths on BOT basis. The KPT has awarded the project of construction of multipurpose cargo berth No.13 at KPT to M/s.Ras Infraport Private Limited (RIPL) and entered into a Concession Agreement on 3 December 2009 for a period of 30 years.
- (ii). As brought out earlier, Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff requires the private operator to approach this Authority for notification of the Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations. Accordingly, the RIPL has approached this Authority with a request to notify the Scale of Rates as required under the Tariff Guidelines of 2008.
- (iii). As reported by the RIPL, the operator expects that the commercial operations will commence w.e.f. 21 January 2013. Relying on the position reported by RIPL, this Authority is inclined to entertain the proposal of RIPL for notification of the Scale of Rates approved in October 2008 subject to adjustment with reference to the indexation of the rates so approved to WPI to the extent of 60%.
- (iv). The KPT, being the Licensor, from whom comments on the proposal of RIPL were sought has furnished its comments on the proposed Scale of Rates, which are discussed below:
 - (a). As rightly pointed out by KPT, the Scale of Rates proposed by the RIPL does not contain Sections 1.1 (Definitions) and 1.2 (General terms and conditions) of the Scale of Rates notified along with the upfront tariff order dated 14 October 2008. These Sections are restored in the draft Scale of Rates proposed by RIPL.
 - (b). With reference to the question raised by the KPT whether the RIPL will handle thermal coal or not, the Scale of Rates notified vide upfront tariff order dated 14 October 2008 includes the cargo "Thermal Coal".
 - (c). With reference to the time of incidence of berth hire, the period of berth hire shall be calculated from the time vessel occupies the berth as stipulated in Note (i) to Section 2 (Berth Hire charges).
 - (d). The deficiencies pointed out by KPT in the second line of Note (v) to Section 2 (Berth Hire charges) and in the first line of Note (iii) to Section 2 (Berth Hire charges) in the Scale of Rates proposed by RIPL appear to be typographical error and are rectified.

- (e). The sentence "The storage charges for the cargo stored in the stackyard beyond the free period allowed shall be as below" appearing in Section 4 (Storage charges) of the Scale of Rates notified in the Upfront tariff order of October 2008 is missing in the draft Scale of Rates proposed by the RIPL as pointed out by the KPT. The said sentence is restored in the Scale of Rates.
- (f). The KPT has requested to indicate when the Scale of Rates will come into force. Since the BOT operator must be in a position to levy the charges from the day the operator commences his commercial operation, it is appropriate that the Scale of Rates is made effective from the date of commencement of commercial operations at the Berth No.13 of the KPT.
- (g). With reference to the suggestions made by the KPT that the base year to be considered for application of escalation factor should be 2012 and not 2008, it is stated that as per Section 6 [General Note to Schedule (2) to (5)] of the Scale of Rates of the upfront tariff order of October 2008 the variation in the WPI occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year to the extent of 60% should be applied on the tariff caps notified in 2008.
- (h). The KPT has suggested some corrections in the mention made by the RIPL in its covering letter with regard to levy of vessel related charges by KPT except berth hire charges. Levy and collection of vessel related charges except berth hire by KPT on the vessels that may visit the Berth No.13 is governed by the Concession Agreement entered between KPT and RIPL and not by the Scale of Rates notified under the upfront tariff order of October 2008.
- (v). As per Clause 2.9.2. of the Tariff Guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by this Authority for the private operator as per Clause 2.9.1 should be in line with the tariff caps prescribed for the Port and included in the bid document, subject to indexation as explained earlier. The Appendix - 12 to the Concession Agreement entered by RIPL with KPT is seen to be the Scale of Rates notified by this Authority under cover of the tariff Order dated 14 October 2008 fixing upfront tariff for construction of four multipurpose cargo berths, read with Corrigendum dated 28 July 2009.
- (vi). With reference to the indexation of the upfront tariff fixed vide Order dated 14 October 2008 as required under Clause 2.8. of the 2008 Guidelines, an escalation factor of 20.11% is to be applied on the tariff caps notified in November 2008. Applying the escalation factor of 20.11% on the tariff caps notified in November 2008, the Scale of Rates implementable by the RIPL is drawn up along with the conditionalities governing the application of rates as prescribed in the tariff Order of October 2008. It is to be noted here that only the rates of tariff items notified vide Order of October 2008 have been subjected to change in view of the application of applicable escalation factor and all the conditionalities governing the application of the rates as contained in Order of October 2008 remain without any change.
- (vii). As stipulated in para 10.3 of the Tariff Order of October 2008, as per Clause 3.8.5. of the Guidelines, if any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the operator.
- (viii). The RIPL is expected to perform at least at the performance norms brought out in the bid documents / concession agreement. The actual performance of the RIPL will be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority will enquire into such allegation and forward its findings to the Kandla Port Trust. If any action is to be taken against the RIPL, the Kandla Port Trust shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the Concession Agreement.
- (ix). During the commercial operation at the terminal, within 15 days from the end of every quarter, the RIPL shall submit to this Authority through the Kandla Port Trust a report

containing the berth's physical and financial performance during the preceding three months.

6.2. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority notifies the Scale of Rates for the Multipurpose Berth No.13 to be operated by the RIPL at KPT attached as **Annex**.

6.3. The Scale of Rates notified for RIPL will come into force from the date of commencement of commercial operations by RIPL at KPT.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/12/Exty.]

ANNEX

Ras Infraport Private Limited
SCALE OF RATES

1.1. DEFINITIONS

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i). "Coastal Vessel" means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the competent authority.
- (ii). "Foreign Vessel" means any vessel other than a coastal vessel.
- (iii). "Per day" means per calendar day unless other wise stated.

1.2. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- (i). The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is 'coastal' or 'foreign-going' for the purpose of levy of vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (ii).
 - (a). The vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.
 - (b). The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
 - (c). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from / to quay to / from storage yard including wharfage.
 - (d). Cargo from a foreign port, which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transshipment to Indian Port 'B' will be, levied the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from / to Indian ports carried by vessel permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (iii). Interest on delayed payments / refunds:
 - (a). The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.
 - (b). The rate of penal interest will be 2% above the Prime Lending Rate of the State Bank of India.
 - (c). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.

- (d). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the Terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in this Scale of Rates.
- (iv). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (v). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the terminal operator.

2. BERTH HIRE CHARGES:

The berth hire charge payable by masters / owners / agents of the vessel and other floating craft approaching or lying alongside the berth shall be as per the rates given below:

Sl. No.	Vessels	Rate per GRT per hour or part thereof	
		Foreign Going Vessel (in Re.)	Coastal Vessel (in Re.)
1.	All vessels	1.18	0.71

Notes:

- (i). The period of berth hire shall be calculated from the time vessel occupies the berth.
- (ii). Berth hire includes charges for services rendered at the berth, such as occupation of berth, rubbish removal, cleaning of berths, fire watch, etc.
- (iii). No berth hire shall be levied for the period when the vessel idles at its berth for continuous one hour or more due to breakdown of terminal operator's equipment or power or for any other reasons attributable to the terminal operator.
- (iv). (a). Berth hire shall stop 4 hours after the time of vessel signaling its readiness to sail.
- (b). The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather, and due to lack of night navigation.
- (c). The master / agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favorable tidal and weather conditions.
- (v). The Penal Berth hire shall be equal to one-day's (24 hours) berth hire charge for a false signal.

"False signal" would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes the signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions."

3. CARGO HANDLING CHARGES:

The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:

Sl. No.	Commodity	Rate in Rupees (Per Tonne)	
		Foreign	Coastal
(a).	Foodgrains and Fertilisers	227.22	136.34
(b).	Thermal Coal	170.33	170.33
(c).	Coal (other than thermal coal), Limestone, Minerals, Sugar, Salt, etc.	170.33	102.20
(d).	Other dry bulk	378.30	226.98
(e).	Steel and Bagged cargo	425.84	255.51
(f).	Timber Logs	681.72	409.03

Note:

The handling charges prescribed above is a composite charge for (i) unloading of the cargo from the vessel including stevedoring and transfer of the same upto the point of storage, storage at the stackyard upto a free period of 5 days and loading on to trucks in respect of import cargo and (ii) unloading of the cargo from the trucks at the stackyard, storage at the stackyard upto a period of 15 days, transfer the cargo to the loading point and loading onto the ship including stevedoring. This composite charge includes wharfage and supply of labour, wherever necessary.

4. STORAGE CHARGES:

The storage charges for the cargo stored in the stackyard beyond the free period allowed shall be as below:

(A). For import**(Rate in ₹ per MT per day)**

Sl. No.	Commodity	Rate for sixth day to twelfth day	Rate for thirteenth day to nineteenth day	Rate for twentieth day onwards
(a).	All types of cargo	12.01	18.02	24.02

(B). For export**(Rate in ₹ per MT per day)**

Sl. No.	Commodity	Rate for sixteenth day to twenty-second day	Rate for twenty-third day to twenty-ninth day	Rate for thirtieth day onwards
(a).	All types of cargo	12.01	18.02	24.02

Notes for Sections 4 (A) and 4 (B) above:

- (i). Five free days for import cargo and fifteen free days for export cargo shall be allowed. For the purpose of calculation of free period, Customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded.
- (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non- working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (iii). Storage charge on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator.

5. MISCELLANEOUS CHARGES

Sl. No.	Commodity	Rate in Rupees (per tonne)
(a).	All types of cargo	18.69

The miscellaneous charges prescribed above is a composite charge for provision of all miscellaneous services such as sweeping of cargo on the wharf, weighment of cargo, dust suppression etc.

6. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (5) ABOVE:

The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.
